



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १ अप्रैल, 1991/११ चंद्र, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

No. 100/1/91

following regulation No. 2, 30 मार्च, 1991

before

संख्या 12-1/89-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित रोजगार अवसायों में कार्यरत अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी रुपये 20/- प्रतिदिन या रुपये 600/- प्रतिमाह से बढ़ा कर रुपये 22/- प्रतिदिन या रुपये 660/- प्रतिमाह कर दी जाये:—

1. कृषि ।
2. भवन एवं सड़क किया निर्माण और अनुरक्षण ।
3. पत्थर पिसाई/कर्णिंग/पत्थर तुड़ान ।
4. बन एवं काल्प क्रिया ।

5. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट ।
6. दुकाने तथा वाणिज्य संस्थान ।
7. रासायन तथा रासायनिक उत्पाद ।
8. इन्जिनियरिंग उद्योग ।
9. खाद्य एवं पेय पदार्थ ।
10. गलीचा व शाल बुनाई ।
11. वस्त्र एवं हौजरी उद्योग ।
12. कागज तथा कागज उत्पाद ।
13. ईंट भट्ठा उद्योग ।
14. लकड़ी पर आधारित तथा फर्नीचर उद्योग ।
15. चाय बागान ।
16. विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजन जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में परिभाषित है ।
17. मच्च निर्माण शालाओं, शराब कारखानों और अन्य अनुसंधिक प्रचालनों जैसे वौतले भरने में नियोजन ।
18. सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पाद में नियोजन ।
19. आरा मशीनों में नियोजन ।
20. निजि शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन ।

2. समान रूप से, उक्त सभी रोजगार व्यवसायों में कार्यरत अर्धकुशल, कुशल तथा उच्च-कुशल तथा अन्य श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी भी 10 प्रतिशत बढ़ाई जाये ।

3. इनके अतिरिक्त जो मजदूर जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, भवन एवं सड़क क्रिया निर्माण और अनुरक्षण, पत्थर पिसाई/क्रीशम/पत्थर तुड़ान और बन एवं काठ क्रिया के रोजगार व्यवसायों में कार्यरत हैं उन्हें 25 प्रतिशत तथा  $12\frac{1}{2}$  प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी में दी जाएगी । जो मजदूर सुरंगों में कार्यरत है उन्हें पहले की तरह 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी लगातार रहेगी ।

4. अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम बेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अनुसरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों को सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिन्हें उक्त प्रस्ताव से प्रस्तावित होने की सम्भावना/उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो उसे शमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को इस प्रस्ताव के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से दो महीने के भीतर भेजें ।

5. संशोधित दरे 1 अप्रैल, 1991 से लागू होंगी ।

आदेशानुसार,

पी० आई० सुवर्तन,  
आयुक्त एवं सचिव ।